

सुखा और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

[विवियन बोस, जगन्नाथदास और चंद्रसेखर अय्यर, जे. जे.]

गैरकानूनी सभा- सामान्य इरादा "और" सामान्य उद्देश्य "-तथ्य न्यायालय का कर्तव्य-भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम एक्सएलवी), एस. एस. 84., 149।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य आशय और धारा 149 के तहत निर्धारित सामान्य उद्देश्य, हालांकि वे कभी-कभी ओवरलैप होते हैं, विभिन्न अर्थों में उपयोग किए जाते हैं और उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। धारा 149 के तहत एक मामले में एक पूर्व सभा और विचारों का मिलन की आवश्यकता नहीं है, यह पर्याप्त है कि प्रत्येक के पास एक ही उद्देश्य है और उनकी संख्या पांच या उससे अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा हैं।

जब भीड़ इकट्ठा होती है और हंगामा होता है और लोग मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए जो भी हथियार वे छीन सकते हैं, उनके साथ घटनास्थल पर भागना स्वाभाविक है। कुछ का उद्देश्य गैरकानूनी हो सकता है लेकिन अन्य का नहीं हो सकता है, और ऐसी

परिस्थितियों में यह कहना असंभव है कि वे सभी एक पूर्व सभा कार्यक्रम के एक सामान्य इरादे से प्रेरित थे।

अदालत को ऐसे तथ्य में क्या करना चाहिए, यह साक्ष्य से पता लगाना कि उनमें से किसके पास व्यक्तिगत रूप से एक गैरकानूनी उद्देश्य था, या मूल रूप से एक वैध उद्देश्य को देखते हुए इसे बाद में गैरकानूनी के रूप में विकसित किया गया था और यदि यह पाता है कि ऐसे पांच या अधिक व्यक्ति थे जिन्होंने एक साथ काम किया था तो एक अवैधानिक सभा होगी।

नतीजतन, एक ऐसे मामले में जहां ऐसी परिस्थितियां थीं जिनसे वास्तव में अदालतें यह अनुमान लगा सकती थीं कि लड़ाई शुरू होने के बाद इसे साझा करने के लिए एक से अधिक के साथ एक गैरकानूनी लक्ष्य विकसित हुआ और वे संतुष्ट थे कि ऐसा हुआ, उनके वर्तमान निर्णयों को अलग करने का कोई कारण नहीं था।

यह न्यायालय पूर्वाग्रह के प्रश्न पर विचार करने में देरी करेगा जब विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है; साथ ही, इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपत्ति को प्रारंभिक चरण में नहीं लिया गया था।

आपराधिक अपील क्षेत्रधिकार: 1955 की आपराधिक अपील सं. 133

1952 के मूल आपराधिक मामले संख्या 1 में मेडता के सत्र न्यायाधीश न्यायालय के 26 मई 1953 के निर्णय और आदेश से 1953 के

आपराधिक अपील संख्या 57 और 83 में जोधपुर में उच्च न्यायालय के 10 जनवरी 1955 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलार्थियों के लिए जय गोपाल सेठी, के. आर. कृष्णस्वामी और के. आर. चौधरी।

प्रत्यर्थी की ओर से पोरस ए. मेहता और पी. जी. गोखले।

5 अप्रैल 1956

न्यायालय का निर्णय बोस जे. द्वारा दिया गया था।

21 जुलाई 1951 की रात लगभग 11 बजे चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह धनकोली गाँव में हुए दंगों का परिणाम बताया गया था। छत्तीस व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से दो की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई। शेष सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325/149 के तहत आरोप लगाया गया था और ग्यारह पर भी धारा 302/149 के तहत आरोप लगाया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धारा 325/149 के तहत पँचिंश आरोपों को बरी कर दिया और नौ को दोषी ठहराया। उन्होंने उन सभी ग्यारह लोगों को बरी कर दिया जिन पर धारा 302/149 के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन उनमें से नौ को धारा 325/149 के तहत दोषी ठहराया गया था।

राज्य ने धारा 325/149 के तहत पच्चीस लोगों को बरी करने के खिलाफ अपील नहीं की और न ही उसने धारा 302/149 के तहत

आरोपित ग्यारह में से दो को बरी करने के खिलाफ अपील की, लेकिन उसने धारा 325/149 के तहत दोषी ठहराए गए शेष नौ लोगों को बरी करने के खिलाफ अपील की। इन नौ दोषियों ने भी अपील की। इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें थीं, एक धारा 302/149 के तहत नौ व्यक्तियों को बरी करने के खिलाफ और दूसरी धारा 325/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा।

उच्च न्यायालय ने दोषियों की अपील को खारिज कर दिया और राज्य की अपील को स्वीकार कर लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत इन नौ व्यक्तियों की दोषसिद्धि को तदनुसार बदल दिया गया और प्रत्येक को निर्वासन की कम सजा दी गई।

दोनों तरफ से यह माना जाता है कि गांव धनकोली में एक तरफ बाउरी के नाम से जानी जाने वाली जाति और दूसरी तरफ गांव की तीन अन्य जातियाँ जाट, धोबी और खती के बीच रक्तपात था।

अभियोजन पक्ष के लिए मामला यह है कि यह एक खेत पर विवाद के कारण था जो कुछ जाटों का था। उस क्षेत्र के बारे में कुछ अदालती कार्यवाही हुई थी जिसमें पारसिया (मारे गए बायोरियों में से एक) जाटों के खिलाफ पेश हुआ था। अभियुक्त सुखा, गुमाना, बेगला और गोविंदा इस क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि रखते थे और इसलिए उन्हें पारसिया के खिलाफ दुर्भावना थी। बचाव पक्ष भी दुश्मनी का आरोप लगाता है। उनका मामला

यह है कि दुश्मनी इस तथ्य के कारण है कि ग्रामीणों ने गाँव में निगरानी के काम के लिए बाउरी को नियुक्त नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें संदेह था कि वहाँ हुई कुछ चोरी के लिए बाउरी जिम्मेदार थे। इसलिए गाँव की अन्य जातियाँ बारी-बारी से यह काम खुद करती थीं। बाउरी लोगों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि लड़ाई के लिए बाउरी जिम्मेदार थे और उन्होंने गाँव के कुछ अन्य लोगों पर हमला किया और इसके कारण लड़ाई हुई; लेकिन किसी भी अपीलकर्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।

इस बिंदु से कथा को क्रमांकित चरणों की एक श्रृंखला में विभाजित करना सुविधाजनक होगा।

1. विचाराधीन दिन, बावरी में से दो, चोटिया और पारसिया, एक नीलामी में बोली लगाने के लिए पड़ोसी गाँव गए थे, जहाँ अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाद पैदा करने वाले खेत को बेचा जा रहा था। वे लगभग 11 बजे अपने गाँव लौटे और आरोपी सुखा और गुमाना (दोनों जाट) से मिले। उन्हें चुनौती दी गई और जब उन्होंने खुलासा किया कि वे कौन थे, तो सुखा और गुमाना ने चिल्लाया "उन्हें मार डालो।" वे खेत की नीलामी के लिए गए थे। उस पर सुखा ने एक बंदूक चलाई जो उसके पास थी और पारसिया के पैरों पर वार किया। पारसिया गिर गया और गुमाना ने उसके सिर पर तलवार से वार किया। उसने चोटिया के सिर पर तलवार से भी वार किया और चोटिया भी गिर गया।

2. पारसिया और चोटिया ने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया और उनके रोने के साथ-साथ बंदूक की गोली की आवाज कई लोगों को घटनास्थल पर ले आई। संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। छोटिया (पीडब्लू 8) का कहना है 30 से 35, रुगा (पीडब्लू 1) का कहना है 50 या 60, बेड़ू (पीडब्लू 2) का कहना है 30 या 40 और इसी तरह लच्छुरी (पीडब्लू 10) का भी कहना है, जबकि लाडिया (पीडब्लू 11) का मानना है कि 100 से 150 थे। अन्य अनुमान भी हैं, ज्यादातर 30 से 40 के पड़ोस में, लेकिन सटीक संख्या मायने नहीं रखती क्योंकि यह स्पष्ट है कि भीड़ जमा हो गई थी। कहा जाता है कि हमला करने वालों की उम्र लगभग 30

या 40 थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि कई बायोरी वहां थे और उनमें से कुछ पर हमला किया गया था।

इन तथ्यों पर जोर देने का उद्देश्य इस तथ्य को सामने लाना है कि वहां के अधिकांश व्यक्ति गैरकानूनी उद्देश्य से इकट्ठा नहीं हुए थे और इसलिए उन्होंने गैरकानूनी सभा नहीं की थी। समस्या यह है कि "उन लोगों को, जिन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, उन लोगों से अलग किया जाए जिन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री सेठी ने तर्क दिया कि इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि एक गैरकानूनी सभा थी क्योंकि यह निर्धारित करना असंभव है कि कौन हमला करने आया था और कौन नहीं। लेकिन हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। वर्तमान में, हम अभियोजन मामले को रेखांकित करते हुए अपने कथन को जारी रखेंगे।

3. जब बंदूक चलाई गई और पारसिया और चोटिया को मार गिराया गया, तो बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उनमें से लगभग 30 या 40 विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस थे। इनमें से कमला, बलिया, टोडिया और भावना (सभी जाट) के पास फारसी थे, गुमाना, गोविंद और जोधिया (जाट भी) के पास तलवारें थीं और बाकी (जाट, धोबी और खती) के पास लाठियां थीं। इन लोगों ने चोटिया और पारसिया पर भी हमला किया।

4. चोटिया और पारसिया के रोने ने माना, गोविंदा, पेमला, राम बक्सा और गंगली और कुछ अन्य लोगों को आकर्षित किया। ये लोग बाउरी हैं। 30 या 40 की इस भीड़ ने माना और गोविंदा पर हमला कर दिया। सुखा ने फिर अपनी बंदूक से दूसरी बार गोली चलाई और माना के बाएं हाथ पर वार किया।

5. इस बीच, गणेश और उनकी पत्नी सेरूरी (बायोरी) आए और कहा, "मत मारो, मत मारो।" सुखा और गुमाना ने कहा कि उन्हें भी पीटा जाना चाहिए और फिर इन 30 या 40 लोगों ने उन्हें भी पीटना शुरू कर दिया और वे नीचे गिर गए।

6. इसके बाद, पारसिया की पत्नी लच्छुरी वहाँ आई और मूल 30 या 40 में से लगभग 10 या 11 लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन वह भाग गई और मामूली पिटाई के साथ भागने में सफल रही।

7. जब यह हो रहा था, तब जमीन पर गिर गए पाँच बाउरी (पारसी, गणेश, माना, गोविंदा और सेरूरी) चिल्लाने लगे। लच्छुरी का पीछा करने वाले दस या ग्यारह लोग वापस आ गए और जमीन पर इन पाँचों के रोने की आवाज सुनकर, सुखा और गुमाना ने कहा कि वे रो रहे थे और उन्हें पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। इस पर ये ग्यारह लोग तीन समूहों में विभाजित हो गए और पाँचों निम्नानुसार हमला कर दिया:

पारसिया को सुखा (फारसी), जीवन (डांगरी) और चोकला (डांगरी) ने पीटा था। माना और गोविंदा को गुमाना (तलवार), बलिया (फारसी) और जनकिया और नारायणा (लाठियों) से पीटा गया था। गणेश को भावना (डांगरी), गोविंदा (तलवार), कुमला और बेगला (डांगरी) ने पीटा था। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। अभियुक्तों पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए थे। 25 व्यक्तियों के एक समूह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325/149 के तहत अन्य अभियुक्तों के साथ जानबूझकर पीटने का आरोप लगाया गया था।

1. छोटीया 2. सेरूरी 3. पारसिया 4. माना 5. गोविंदा और 6. गणेश।

बाद के चरण में, निम्नलिखित वाक्य को आरोप में जोड़ा गया: "जिसे आपने एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में उसके सामान्य इरादे के अभियोजन में लगाया था। इन पचिश लोगों को बरी कर दिया गया था और हम उनसे चिंतित नहीं हैं सिवाय इस बात के कि वे घटना के उस हिस्से से संबंधित नहीं थे जिसे हमने ऊपर 6 और 7 चरणों के रूप में निर्धारित किया है। शेष ग्यारह के खिलाफ आरोप को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले के तहत, सुखा को छोड़कर प्रत्येक पर, अन्य अभियुक्तों के साथ बाउरी पारसिया, माना, गोविंदा, गणेश, चोटिया, सेरूरी आदि को पीटने का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि ग्यारह में से पाँच ने उन्हें "तलवारों और लाठियों" से पीटा था; अन्य

पाँच ने "लाठियों आदि से"। जबकि ग्यारहवें, सुखा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पारसिया और माना पर गोली चलाई थी "जिसके परिणामस्वरूप वे गिर गए।" फिर प्रत्येक आरोप जारी रहता है-"और जब इन चोटों के परिणामस्वरूप सभी गिर गए थे।" उसके बाद आरोप तीन समूहों में विभाजित हो जाते हैं: एक समूह (1) गुमाना, (2) नारायणा, (3) बलिया और (4) जांकिया पर गोविंदा और माना को पीटने का आरोप लगाता है, "जो उन्हें मारने के इरादे से लाठियों से कराह रहे थे, जब तक कि वे वास्तव में मारे नहीं गए।" अगला समूह (1) जीवन, (2) सुखा और (3) चोखला पर आरोप लगाता है कि वे पारसिया को "उसकी मृत्यु तक हत्या करने के इरादे से" लाठी से मारते हैं। तीसरा समूह (1) बेगला, (2) गोविंदा, (3) कुमला और (4) भावना पर गणेश की हत्या करने के इरादे से लाठी से हमला करने का आरोप लगाता है।

इनमें से प्रत्येक आरोप के अंत में निम्नलिखित वाक्य भी जोड़ा गया था: "और आपने अपने सामान्य इरादे के अभियोजन में एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में ऐसा किया था।" सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में "सामान्य इरादे" और "सामान्य उद्देश्य" के बीच कुछ भ्रम रहा है। यह सच है कि दोनों कभी-कभी ओवरलैप होते हैं लेकिन उनका उपयोग कानून में अलग-अलग अर्थों में किया जाता है और उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। गैरकानूनी सभा या दंगे के मामले में हम एक सामान्य उद्देश्य से चिंतित हैं। हालाँकि, हम संतुष्ट हैं कि इससे कोई पूर्वाग्रह

पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हमने इन आरोपों को कुछ हद तक निर्धारित करने का कारण यह है कि अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दो अलग-अलग सभाएँ थीं, जिनमें से एक पच्चीस व्यक्तियों में से छह विशिष्ट व्यक्तियों को पीटने के लिए और ग्यारह में से एक अन्य तीन समूहों में उन्हें मारने के लिए था। उन्होंने तर्क दिया कि पहली सभा का गठन करने वाले पचिस लोगों को बरी कर दिया गया है; कि एकमात्र सामग्री जिससे दूसरे मामले में एक गैरकानूनी सभा का अनुमान लगाया जा सकता है, वह है लच्छुरी का पीछा करके लौटने के बाद दूसरी बार सुखा और गुमाना को उकसाना। उन्होंने कहा कि उस कहानी पर विश्वास नहीं किया गया है, इसलिए सभी को बरी कर दिया जाना चाहिए। मामले के इस हिस्से पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि "जो भी पिटाई की गई थी, वह भोटिया और पारसिया और सुखा और गुमाना और गुमाना और नरैना और मौके पर पहुंचे अभियुक्तों के बीच हाथापाई के तुरंत बाद की गई थी। किसी ने किसी को उकसाया नहीं। (पैरा 103)। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने के बारे में साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालाँकि, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि यह मार्ग दूसरे उकसावे को संदर्भित करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ग्यारह लोगों ने लच्छुरी का पीछा किया और उसे पीटा और जमीन पर पड़े अन्य लोगों को खत्म करने के लिए लौट आए। हम सोचते हैं कि यह सही है।

अपने फैसले के पैराग्राफ 101 में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य को निर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह घटनाओं को दो भागों में विभाजित करते हैं: एक जिसमें एक बड़ी सभा ने सभी घायल व्यक्तियों को पीटा और दूसरी जिसमें ग्यारह ने सुखा और गुमाना के उकसावे पर चार मृत व्यक्तियों को मार डाला। पैराग्राफ 102 में उन्होंने कारण बताए कि वे इस कहानी पर विश्वास क्यों नहीं कर पाए। पहला इसलिए कि "लाडिया (पीडब्लू 11) ने पुलिस के सामने अपने बयान में यह नहीं कहा कि लच्छुरी को पीटने के बाद जब दस या ग्यारह लोग लौट आए तो सुखा और गुमाना के उकसावे पर घायलों को फिर से पीट-पीटकर मार दिया गया।" न्यायाधीश पैराग्राफ 103 में बताए गए निष्कर्ष पर पहुंचे। पैराग्राफ 117 में उन्होंने कहा-"बेगला और गोविंदा को छोड़कर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि सुखा, गुमाना, नारायणा, कुमला, बलिया, जीवन, चोखला, भावना खाती और जनकिया ने बाउरी को मारने के सामान्य उद्देश्य से दंगे किए थे।" पैराग्राफ 118 में उन्होंने कहा-"मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन सभी अभियुक्तों का इरादा पूरे बाओरी लोगों की हत्या करना था।" पैरा 119 में-"अभियुक्त ने घायलों को जोरदार पीटा।" उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मारने के लिए किसी भी सामान्य उद्देश्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उनका मानना था कि पीटने के लिए एक सामान्य उद्देश्य स्पष्ट था। चूंकि वह यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि किस आरोपी ने घातक प्रहार किए, इसलिए उसने सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा

149 के साथ धारा 304 के तहत दोषी ठहराया। हम समझते हैं कि इस फैसले से, जिसे समग्र रूप से पढ़ा जाए, यह स्पष्ट है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने किसी भी स्तर पर उकसावे की कहानी पर विश्वास नहीं किया क्योंकि अगर वह पहले उकसावे पर भी विश्वास करते, तो हत्या करने का एक सामान्य उद्देश्य सामने आता। दुर्भाग्य से हम उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से बहुत अधिक सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया है और एक सामान्य वस्तु के बारे में स्पष्ट निष्कर्षों तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि कुछ हद तक इस तथ्य के कारण कि उन्होंने एक सामान्य वस्तु और एक सामान्य इरादे के बीच के अंतर की सराहना नहीं की है। उनका मानना है कि छह गवाहों पर इस हद तक भरोसा किया जा सकता है कि "ग्रामीण बंदूकों, तलवारों, फारसी और लाठियों से लैस थे"। वे उन सभी पर विश्वास नहीं करते हैं जो ये गवाह कहते हैं क्योंकि वे मानते हैं "हालांकि, इसलिए, हम यह नहीं मानते हैं कि इन ग्यारह व्यक्तियों ने जानबूझकर चार घायल बाउरी की हत्या कर दी थी जो यह कहते हुए वहां लेटे हुए थे कि उन्हें मार दिया जाना चाहिए, हमारे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि इन ग्यारह व्यक्तियों *ftu* सभी का उल्लेख इन छह गवाहों द्वारा किया गया है जो निश्चित रूप से इस घटना में अधिक सक्रिय भाग लेते देखे गए थे।" फिर वे जारी रखते हैं - इसलिए हम इन गवाहों के बयानों से संतुष्ट हैं कि घटना मुख्य रूप से उनके द्वारा कही गई थी और अभियोजन पक्ष ने

मामले का सही विवरण दिया है। इसके बाद, उनका मानना है कि यह तथ्य कि नौ अपीलार्थियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न हथियारों से लैस होकर तुरंत सामने आए, उन्होंने एक सहायक पर चोटिया और पारसिया और दूसरे पर गुमाना के बीच झगड़े को सुना "यह दर्शाता है कि पहले से कुछ परामर्श हुआ होगा और ये व्यक्ति आम विषय के अभियोजन में आए होंगे।" और वे इस कारण को जोड़ते हैं: "अभियोजन पक्ष के गवाहों के पास यह भी सबूत है कि जैसे ही बाउरी आए, इनमें से किसी न किसी आरोपी ने बाकी ग्रामीणों को बाउरी को पीटने के लिए उकसाया।" इससे वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बायोरियों को पीटने के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा थी। यह बहुत असंतोषजनक है। विद्वान न्यायाधीश बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील पर विचार कर रहे थे और हालांकि उन्होंने अपील की अनुमति दी है, वे इस बारे में विशिष्ट नहीं हैं कि वे अपने निष्कर्षों के समर्थन में साक्ष्य के किस हिस्से पर भरोसा करते हैं, और न ही उनके निष्कर्ष उस परिसर से तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं जिस पर वे आधारित हैं। उदाहरण के लिए, पूर्व परामर्श के बारे में निष्कर्ष लें। सबसे पहले, जब कोई सामान्य उद्देश्य विचाराधीन हो तो किसी पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य उद्देश्य और सामान्य इरादे के बीच अंतर का सार वहीं निहित है। अगले स्थान पर, छह गवाह, जिन पर भरोसा किया जाता है, कहते हैं कि 30 या 40 व्यक्तियों की भीड़ जमा हो गई थी। उस भीड़ में बाउरी भी थे क्योंकि तीन बाउरी (पारसिया

और चोटिया के अलावा) मारे गए थे और अन्य घायल हो गए थे। यह भी स्पष्ट है कि इनमें से कुछ बाउरी के पास किसी न किसी प्रकार के हथियार होंगे क्योंकि तीन अभियुक्तों के बेटे पर मामूली चोटें आई थीं और एक को फ्रैक्चर हुआ था। सबूतों से पता चलता है कि गाँव में चोरी हुई थी। यह हंगामा रात 11 बजे हुआ। उन परिस्थितियों में, ग्रामीणों के लिए यह स्वाभाविक होगा कि वे घटनास्थल पर दौड़ें और जो कुछ भी हाथ में आए, उससे खुद को लैस करें। हो सकता है कि कुछ लोग गैरकानूनी उद्देश्य से प्रेरित हुए हों, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसी परिस्थितियों में पूर्व कार्यक्रम के साथ एक सामान्य इरादे का अनुमान लगाना असंभव है।

एक आम उद्देश्य अलग है और वास्तव में अदालतें उन सबूतों पर निष्कर्ष निकालने की हकदार हैं जो स्वीकार किए गए हैं कि घटनास्थल पर जाने वालों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों को पीटने के उद्देश्य से गए थे जिन्हें वे चोर समझते थे और न केवल उन्हें पकड़ने या उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए; दूसरे शब्दों में, कि उनमें से कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से एक गैरकानूनी उद्देश्य था। यदि प्रत्येक का एक ही उद्देश्य होता, तो उनका उद्देश्य समान होता और यदि इस उद्देश्य के साथ पाँच या उससे अधिक होते, तो वे आपस में बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के एक गैरकानूनी सभा का गठन करते। इसके बाद, उकसाने के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को लें। उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान को खारिज कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि दूसरी

पिटाई के बारे में कहानी एक सुधार है और यह भी कि वे उन सबूतों पर विश्वास नहीं करते हैं जो इंगित करते हैं कि इन ग्यारह व्यक्तियों ने जानबूझकर चार घायल बाउरी की हत्या कर दी थी। लेकिन उकसावे के बारे में एकमात्र सबूत यह है कि सुखा और गुमाना ने दूसरों को बरसिया को मारने और बाद में दूसरों को मारने के लिए कहा। यह उकसावा स्पष्ट रूप से मारने के लिए था, न कि केवल पीटने के लिए। यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उकसाने के बारे में कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें यह जानने के लिए अंधेरे में छोड़ दिया जाता है कि विद्वान न्यायाधीश अपने निष्कर्ष के आधार पर क्या कहते हैं। इसने हमें यह पता लगाने का काम दिया है कि क्या इन दोषसिद्धि के लिए कोई उचित आधार है या नहीं। अब, जैसा कि हम विद्वान सत्र न्यायाधीश को समझते हैं, उन्होंने कहानी के पहले भाग पर विश्वास किया है जिसे हमने चरण संख्या 1 के रूप में निर्धारित किया है, सिवाय उस हिस्से के जो हत्या के लिए उकसाने के बारे में बोलता है। वह पाता है कि एक तरफ सुखा और गुमाना और दूसरी तरफ पारसी और चोटिया के बीच मुलाकात हुई थी। वे कहते हैं-"इस मामले में गवाहों द्वारा बताई गई घटनाओं से सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरुआत में लड़ाई केवल कुछ लोगों के बीच हुई थी और उनके रोने की आवाज सुनकर उनके रिश्तेदार, दोस्त और रिश्तेदार और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुछ ग्रामीणों ने बाउरी को पीटा।" वहाँ रुकने से, यह स्पष्ट है कि जब पिटाई शुरू हुई तो कोई गैरकानूनी सभा

नहीं थी; न ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे उनकी संख्या 30 हो या 150, ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया। इसलिए हमें सबूतों को सावधानीपूर्वक स्कैन करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि उसके बाद क्या हुआ। निष्कर्ष यह है कि जिन ग्यारह अभियुक्तों पर हत्या का आरोप लगाया गया था, वे सभी घायल व्यक्तियों की पिटाई में शामिल थे। यह दंगों के तत्वों में से एक को संतुष्ट करता है, अर्थात् पाँच या अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति। लेकिन निश्चित रूप से यह पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, एक "सभा" होनी चाहिए और उस सभा का एक "सामान्य उद्देश्य" होना चाहिए और उद्देश्य "गैरकानूनी" होना चाहिए।

लेकिन एक आम उद्देश्य एक आम इरादे से अलग है जिसमें हमले से पहले पूर्व कार्यक्रम और लोगों एक आम बैठक की आवश्यकता नहीं होती है, और लोगों के वहां पहुंचने के बाद एक गैरकानूनी वस्तु विकसित हो सकती है। विशेष अवस्था में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना हमारे लिए नहीं है। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनसे वास्तव में अदालतें यह अनुमान लगा सकती हैं कि एक बार कार्य शुरू होने के बाद इसे साझा करने के लिए पांच से अधिक के साथ एक गैरकानूनी वस्तु विकसित हुई; और जैसा कि वास्तव में दो अदालतें संतुष्ट हैं कि उसने किया था, हमारे लिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। जो लोग कानूनी रूप से वहाँ आए थे, पहली बार में, यह सोचकर कि वहाँ चोर

हैं, वे "चोरों" को पकड़ने या उनकी संपत्तियों की रक्षा करने में मदद करने के बजाय उन्हें पीटने का इरादा विकसित कर सकते थे; और यदि पाँच या उससे अधिक लोग वस्तु को साझा करते और पिटाई में शामिल हो जाते, तो प्रत्येक का उद्देश्य आम वस्तु बन जाता।

इसका मतलब यह नहीं है कि उपस्थित सभी लोग उस सभा के सदस्य थे। निर्दोषता का अनुमान इस तरह के निष्कर्ष को रोक देगा। जो लोग प्रकट की गई परिस्थितियों में घटनास्थल पर पहुंचे, उन्हें यह माना जाना चाहिए कि वे एक वैध उद्देश्य के लिए वहां गए थे, भले ही वे सशस्त्र थे। रात में शहर में घुसने वाले लुटेरों की गिरफ्तारी और व्यक्ति और संपत्ति की रक्षा वैध उद्देश्य हैं। लेकिन जब उस उद्देश्य को पार कर दिया जाता है और व्यक्ति संदिग्धों को पीटना शुरू कर देते हैं तो पिटाई का गैरकानूनी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अब पुलिस की तुलना में पीटने और चोरों को सजा देने के हकदार नहीं हैं, खासकर ऐसे समय में जब उनके खिलाफ संदेह से परे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर पाँच या उससे अधिक मूल वैध उद्देश्य से अधिक हैं और प्रत्येक के दिमाग में एक ही गैरकानूनी इरादा है और वे एक साथ काम करते हैं और पिटाई में शामिल होते हैं, तो वे अपने आप में एक गैरकानूनी सभा बनाते हैं। इसके और उस मामले के बीच सैद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं है जिसमें मूल उद्देश्य गैरकानूनी था। अंतर केवल इतना है कि इस तरह के मामले को स्थापित करना अधिक कठिन है और इसकी अधिक सावधानी के साथ जांच की जानी चाहिए। लेकिन वह जांच

यहाँ है और हम संतुष्ट हैं कि इस मामले में ऐसे सबूत हैं जिन पर तथ्य की अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुँच सकती हैं कि वे पहुँच गए हैं।

अब, क्या इन ग्यारह व्यक्तियों ने एक सभा का गठन किया था या क्या वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक साथ जोड़ने के लिए किसी भी सामान्य कारक के बिना थे? हम सोचते हैं कि इसका जवाब देना आसान है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक (सुखा और गुमाना को छोड़कर जो पहले से ही वहाँ थे) पारसी और चोटिया के रोने और लड़ाई के शोर के कारण मौके पर इकट्ठा हो गए। यह उनकी बैठक में एक सामान्य कारक का आयात करता है और उन्हें एक सभा के रूप में जोड़ता है। इकट्ठा करने में उनका उद्देश्य निर्दोष हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि इस तरह के एक सामान्य कारक ने उन्हें एक साथ आने के लिए प्रेरित किया, उन्हें एक "सभा" में गठित करता है, हालांकि केवल उस साक्ष्य पर नहीं, एक गैरकानूनी सभा में। इसके बाद हमें यह देखना होगा कि क्या उनमें से किसी का उद्देश्य गैरकानूनी था। सुखा और गुमाना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से गैरकानूनी था। अब जो सबूत माना जा रहा है, उससे पता चलता है कि अन्य नौ वास्तव में पिटाई में शामिल हो गए थे और उन्होंने ऐसा तब किया जब सुखा ने पारसिया पर अपनी बंदूक चलाई थी और पारसिया जमीन पर गिर गया था। इससे यह भी पता चलता है कि ये अन्य लोग जब उनके समर्थन में आए तो उन्होंने पारसिया के रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर रुख किया। इसलिए, प्रत्येक का मूल उद्देश्य जो भी रहा हो, इसने उस समय उद्देश्य की

एकता हासिल कर ली जब अन्य लोग इसमें शामिल हो गए और सुखा और गुमाना की सहायता करना जारी रखा और पारसिया की मदद के लिए आए अन्य बाउरी लोगों को पीटने में उनकी मदद की। यह छिटपुट छिटपुट कृत्यों का मामला नहीं है, बल्कि उद्देश्य की एक निश्चित निरंतरता का संकेत देता है, प्रत्येक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, अर्थात् या तो सुखा और गुमाना को पारसिया और चोटिया को मारने में मदद करना और जो उनकी मदद करने के लिए आए थे या अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए पिटाई में शामिल होना। लेकिन उद्देश्य की समानता इस तथ्य का एक निष्कर्ष है कि तथ्य की कौन सी अदालतें बनाने की हकदार होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग प्रारंभिक उकसावे के कारण शामिल हुए या क्या, हमले को आगे बढ़ते हुए देखकर, वे अपने दम पर शामिल हुए, क्योंकि जब तक प्रत्येक का उद्देश्य पारसिया और चोटिया और उनकी सहायता के लिए आने वालों को पीटना था, यह उनके उद्देश्य को सामान्य बना देगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा अपेक्षित सामान्य इरादे और धारा 149 में निर्धारित सामान्य उद्देश्य के बीच का अंतर सही है।

धारा 149 के तहत एक मामले में मन की पूर्व बैठक की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि प्रत्येक की दृष्टि में एक ही वस्तु है और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी विशेषताएँ साक्ष्य के उस हिस्से

में पाई जाती हैं जिस पर विश्वास किया गया है। इसलिए, इन निष्कर्षों पर, जिन तक वास्तव में अदालतें पहुंचने की हकदार हैं, सभा का उद्देश्य गैरकानूनी था, लेकिन इस बिंदु तक सर्वोच्च सामान्य विभाजक केवल मारना था न कि मारना। उस समय तक, भारतीय दंड संहिता की धारा 325/149 के तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश की दोषसिद्धि उपलब्ध नहीं है। अगला सवाल यह है कि क्या मामला होने के नाते, धारा 302/149 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय का मानना है कि हत्या करने का कोई सामान्य इरादा था, इसलिए अधिक गंभीर अपराध के लिए दोषसिद्धि केवल धारा 149 के तहत तब कायम रखी जा सकती है जब यह दिखाया जा सके कि (1) हमला किए गए कुछ व्यक्तियों की वास्तविक हत्या उस पिटाई के परिणामस्वरूप होने की संभावना थी जो सामान्य उद्देश्य था और (2) कि इस तरह से दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि यह एक संभावित परिणाम हो सकता है। अब जहाँ तक सुख और गुमना का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। उन्होंने घातक हथियारों से लड़ाई शुरू की। सुखा ने कम से कम दो बार गोली चलाई और दो लोगों को मारा। हो सकता है कि उसका खुद को मारने का कोई इरादा न हो और वास्तव में यह तथ्य कि घाव गैर-महत्वपूर्ण भागों पर हैं, उसका उपयोग उसके पक्ष में एक कारक के रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो रात के उस समय एक आग्नेयास्त्र रखता

है और इसका उपयोग करता है और फिर एक उत्साहित भीड़ के इकट्ठा होने के बाद लड़ाई जारी रखता है और जब उनमें से कम से कम नौ अपने पहले शॉट के बाद पिटाई में शामिल होने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि किसी को घातक प्रहार का सामना करने की संभावना है या कम से कम कि ला से लैस कई व्यक्तियों द्वारा लगाए गए प्रहारों का संचयी प्रभाव सदमे से मौत का कारण बन सकता है। इस तरह के दंगे आम हैं और अक्सर मौतों का परिणाम होता है, इसलिए, न केवल इस तरह से किए गए हमले का एक संभावित परिणाम हत्या थी, बल्कि सुखा और गुमना को सामान्य बुद्धि के लोगों के रूप में यह पता होना चाहिए।

अन्य अपीलार्थियों के मामले में भी लगभग यही विचार लागू होते हैं। वे उन लोगों को मारने के लिए दौड़े जिन पर पहले ही गोली चल चुकी थी और जो जमीन पर गिर गए थे। वे एक भीड़ के बीच में थे जो शायद ही शांत और अभेद्य हो सकती थी और वे कई अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें पीटने लगे। उचित बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि इस तरह के हाथापाई में किसी के मारे जाने की संभावना है। इसलिए, उन्हें भी आवश्यक ज्ञान दिया जा सकता है। दो सवाल बाकी हैं। एक को सबूत के उस हिस्से की विश्वसनीयता के खिलाफ निर्देशित किया गया था जिस पर विश्वास किया गया है। यह तर्क, इसकी सभी पुनरावृत्ति, लंबाई और वाक्पटुता के बावजूद, यह था कि जब किसी गवाह के साक्ष्य के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो उसकी बाकी गवाही पर कार्रवाई करना

असुरक्षित है। इसका उत्तर समान रूप से गलत है, अर्थात् कि वास्तव में न्यायाधीशों को ऐसा करने का अधिकार है और जब यह अनुच्छेद 136 के तहत कार्य करता है तो यह अपील की अदालत नहीं है। इसके बारे में निष्कर्ष समवर्ती हैं, इसलिए, हमारे सामान्य अभ्यास का पालन करते हुए, हम साक्ष्य की समीक्षा करने से इनकार करते हैं। दूसरा यह है कि आरोप में इसकी अनुपस्थिति पूर्वाग्रह का कारण बनी। हमने हाल ही में निर्णय लिया है कि जब विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो हम पूर्वाग्रह के सवाल पर विचार करने में देरी करेंगे; इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपत्ति को शुरुआती चरण में नहीं लिया गया है। इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए यहां उच्च न्यायालय में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में पूर्वाग्रह का कोई संकेत नहीं है; न ही इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति के लिए बहुत लंबी और तर्कपूर्ण याचिका में इसे शिकायत का आधार माना गया था। पूर्वाग्रह के बारे में एकमात्र शिकायत इस आधार पर थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत कोई उचित जांच नहीं की गई थी। हम इस मामले को उठाने की अनुमति देने से इनकार करते हैं। अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक सुनील कुमार की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।